छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जिन गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है उनके जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) ऐसे गांव जिनमें टेलीफोन सुविधा अभी प्रदान की जानी है उनकी संख्या 14,533 है और उनके ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्ष 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अपनाई है जिसमें 1997 तक प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। जैसे जैसे तकनीकी व्यवहार्यता हो रही है, इन सार्वजनिक टेलीफोन पर एस टी डी सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

विवरण

1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जिन गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है उनके जिला-वार ब्यौरे

क्रम सं॰	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या जिनमें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई।		ग्रामों की संख्या जिनमें अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है।
		1993-94	1994-95	
1.	बस्तर	251	161	2908
2.	बिलासपुर	401	232	2341
3.	दुर्ग	204	125	1241
4.	रायगढ़	174	230	1439
5.	रायपुर	256	418	2658
6.	राजनंदगांव	161	130	1847
7.	सरगुजा	67	61	2099
	कुल जोड़	1514	1357	14533

References of Kashmir and Farakka made by Pakistan and Bangladesh in UN

330. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of Pakistan and Bangladesh Prime Ministers repeated references on Kashmir and Farakka issues in their speeches in the United Nations Golden Jubilee Commemorative Session;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) the steps taken to take up the matter with the Governments of Pakistan and Bangladesh so that these issues are not raised by them again; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA):(a) Yes, Sir.

(b) to (d) Government are committed to the resolution of all Indo-Pakistan issues through direct bilateral discussions as envisaged in the Simla Agreement. Government have repeatedly conveyed to Pakistan their desire to resume bilateral discussions without pre-conditions.

Government believes that the Farakka issue is a matter for bilateral discussions and will be appropriately discussed with Bangladesh during bilateral talks.